11.02.2026 आकाशवाणी जयपुर–अजमेर 18.30 पीएम
प्रादेशिक समाचार

- उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प पर केन्द्रित आगामी वर्ष का बजट पेश किया।
- बजट में नई जल नीति, आईटी पॉलिसी और ड्रोन पॉलिसी लाये जाने की घोषणा।
- मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा–पिछले सरकार की तुलना में बीते दो वर्षों में पूंजीगत व्यय को करीब दोगुना बढाया गया।
- राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू होगीं।

000

राज्य के आगामी बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिये 3 हज़ार 427 करोड़ रूपये के पूंजीगत खर्च का प्रस्ताव किया गया है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026–27 का बजट पेश करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य केंद्र 'विकसित राजस्थान 2047' का विजन और अर्थव्यवस्था के दस प्रमुख स्तंभ हैं। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि पिछली सरकार की तुलना में प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है।

000

राज्य सरकार द्वारा इस बजट में कृषि और किसान कल्याण के लिए एक लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि यह राशि राज्य की सकल घरेलू उत्पाद का 5 दशमलव पांच–पांच प्रतिशत है। दिया कुमारी ने कहा कि 35 लाख किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त फसली ऋण दिये जाएंगे। यमुना जल समझौते का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में पानी लाने के लिए 32 हजार करोड़ रुपये की परियोजना के कार्य भी जल्द शुरू होगें। अगले साल किसानों को 50 हजार सोलर पंप दिए जाएंगे और तारबंदी के लिए 50 हजार किसानों को 288 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा।

000

नारी शक्ति और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के संबंध में दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलने वाले ऋण की सीमा 50 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना में ऋण की सीमा को भी बढ़ाकर एक लाख 50 हजार रुपये कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण महिलाओं के रोजगार के लिये 100 करोड़ रुपये की लागत से रूरल वूमेन बीपीओ केंद्र खोले जाएंगे और महिला कार्मिकों के लिए कार्यालयों में मुख्यमंत्री शिशु–वात्सल्य सदन स्थापित होंगे।

000

राज्य के कार्मिकों और पेंशनर्स के हितों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बारे में उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाए यह समिति वेतनमान और पदोन्नति के अवसरों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि 70 वर्ष तक के बुजुर्गों और कर्मचारियों के लिए विशेष सैलरी अकाउंट पैकेज लाया जाएगा, जिसमें रियायती दर पर ऋण और बीमा की सुविधा मिलेगी। प्रशासनिक सुधारों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि उपनिवेशन विभाग को अब राजस्व विभाग में विलय किया जाएगा और 8 नए जिलों में सरकारी कार्यालयों के निर्माण के लिए बजट दिया गया है।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 30 हजार युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। दिया कुमारी ने घोषणा की कि जलदाय विभाग और कृषि विश्वविद्यालयों में विभिन्न पदों पर नई भर्तियां की जाएंगी।

000

उपमुख्यमंत्री ने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ करने को राज्य सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने घोषणा की कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख छात्रों को निशुल्क यूनिफॉर्म देने के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए ई–वाउचर दिए जाएंगे और भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए 'राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी' बनाई जाएगी।
राज्य के इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के तहत नए पुलों और सड़कों के निर्माण पर 1800 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। उन्होंने घोषणा की कि सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री करने के लिए फ्लाईओवर और अंडरपास निर्माण पर 2300 करोड़ रुपये व्यय होंगे, जिसमें जयपुर के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राजमार्गों पर दुर्घटनाएं रोकने के लिये आधुनिक कैमरे लगाये जायेगें।

000

अमृत 2.0 मिशन के तहत अगले साल 3 लाख नए कनेक्शन जारी किए जाएंगे और बीकानेर के देशनोक में 24 घंटे पानी के लिए 750 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

नागरिक सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के संबंध में उपमुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। शहरों में सुरक्षा के लिए 5000 होम गार्ड्स बढ़ाये जायेगें। अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 40 करोड़ रुपये की लागत से 93 फायर बाइक खरीदी जाएंगी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई के लिए एसीबी के फंड को बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का विशेष ध्यान चिकित्सा सुविधाओं और स्वास्थ्य क्षेत्र पर है। उन्होंने बताया कि जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में 75 करोड़ रुपये की लागत से 500 बेड का नया आईपीडी टावर बनाया जाएगा। बड़े शहरों में मरीजों के परिजनों के ठहरने के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से विश्राम गृह बनाए जाएंगे। अस्पताल में मृत्यु होने पर पार्थिव देह को निशुल्क घर पहुँचाने के लिए मोक्षवाहिनी योजना भी शुरू की जाएगी।

उपमुख्यमंत्री ने सीकर, झुंझुनूं, डीग और भरतपुर में एयरपोर्ट बनाने के लिए फिजिबिलिटी सर्वे कराने की घोषणा की। साथ ही जैसलमेर के खुहड़ी में अल्ट्रा लग्जरी पर्यटन जोन और कुलधरा में पर्यटन केंद्र बनेगा। धार्मिक पर्यटन का जिक्र करते हुए उन्होंने जानकारी दी कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 50 हजार बुजुर्गों को ए.सी. ट्रेनों में यात्रा करवाई जाएगी। साथ ही 6 हजार वरिष्ठजनों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ, काठमांडू की यात्रा करवाया जाएगी।
उन्होंने बताया कि जोधपुर में शहीद मेजर शैतान सिंह कौशल विकास केंद्र और झुंझुनूं में वॉर म्यूजियम खोला जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार नई जल नीति, आईटी पॉलिसी और ड्रोन पॉलिसी लेकर आएगी। बजट में अगले साल प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ रुपये की लागत से नए सोलर पार्क बनेंगे। कर सुधारों की जानकारी देते हुए उन्होंने घोषणा की कि कर्ज के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क को एक प्रतिशत से घटाकर आधा प्रतिशत कर दिया गया है।

000

बजट के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को 2047 तक विकसित बनाने के संकल्प के रोड़ मैप को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने वर्ष 2024–25 बजट के करीब 93 फीसदी कार्य वहीं पिछले साल की 86 प्रतिशत बजट घोषणाएं पूरी की जा चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि इस बार के बजट का आकार 6 लाख 10 हजार करोड़ रूपये से अधिक का है, जो कांग्रेस सरकार के अंतिम बजट से 41 प्रतिशत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल की तुलना में उनकी सरकार ने पिछले दो साल में पूंजीगत व्यय करीब दोगुना बढाया है। श्री शर्मा ने कहा कि युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए बजट में कई घोषणाएं की गयी हैं।

000

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इस बजट को आधारहीन बताया और कहा कि कई घोषणाएं ऐसी हैं जिनमें कोई वित्तीय प्रावधान नहीं किया गया है।

000

केन्द्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह ने राज्य के बजट को विकसित भारत के संकल्प में प्रदेश की सशक्त साझेदारी को आगे बढ़ाने वाला दूरदर्शी रोडमैप बताया। श्री शेखावत ने कहा कि यह बजट कला–संस्कृति, पर्यटन, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा और जल उपलब्धता पर समग्र विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी ने बजट को सर्वजन हितैषी बताया।

000

व्यापार और उद्योग जगत के संगठनों ने भी बजट का स्वागत किया है। फैडरेशन आफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्टी के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बजट को प्रदेश की आर्थिक तरक्की को गति देने वाला बताया। उन्होंने कहा कि बजट में कई घोषणाएं की गईं हैं, जो उद्योगों को बढावा देंगी और इसी से राज्य के विकास को रफ्तार मिलेगी।

000

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं कल से शुरू हो रही हैं। इस साल बोर्ड परीक्षाओं के लिए 19 लाख 90 हजार से ज्यादा विद्यार्थी पंजीकृत हैं। परीक्षाओं के लिए प्रदेशभर में 6 हजार 194 केंद्र बनाए गये हैं। बोर्ड ने नकल रहित पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं। इस साल जिलों में अभय कमांड सेंटर्स के माध्यम से परीक्षा केन्द्रों की निगरानी की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बोर्ड परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं।

000

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 22 फरवरी को आकाशवाणी के ''मन की बात'' कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 131वीं कड़ी होगी। इसके लिए सुझाव टोल–फ्री नम्बर 1800–11–7800 पर भेजे जा सकते हैं। नरेन्द्र मोदी एप और माय जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 20 फरवरी तक स्वीकार किए जाएंगे।

000